• गुड न्यूज...

75 साल से ऊपर की आयु वाले पेंशनर्स को एरियर का तोहफा

शिमला : कर्मचारियों की डीए व एरियर की डिमांड को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने 75 और इससे ऊपर की आयु वाले पेंशनर्स को एरियर की घोषणा कर दी है। बुधवार को वित्त विभाग के प्रधान सचिव की तरफ से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया कि पहली जनवरी 2016 से पेंशन/फैमिली पेंशन का संशोधित एरियर तय घोषणा के अनुसार दिया जाएगा। इस संदर्भ में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अगस्त को देहरा में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में घोषणा की थी।

ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि उपरोक्त आयु वर्ग के पेंशनर्स को बकाया एरियर का पचास फीसदी दिया जाएगा। यानी बाकी बचे 45 फीसदी

एरियर का आधा यानी 22.5 फीसदी इसी माह में दे दिया जाएगा। अगस्त 2024 में जिन पेंशनर्स की आयु 75 या इससे अधिक हो गई है, वे इस एरियर के पात्र होंगे।

55 फीसदी एरियर का हो चुका है भुगतान-उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पेंशनरों को 55 फीसदी एरियर का भुगतान कर चुकी है। बकाया एरियर 45 फीसदी है। इस 45 फीसदी में से आधा हिस्सा यानी 22.5 फीसदी इसी माह जारी किया जाएगा। पेंशनर्स के अलावा फैमिली पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। इस बारे में प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी पीडीए यानी पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटीज को निर्देश जारी किए हैं कि पात्र पेंशनर्स को एरियर का भुगतान तय समय में किया जाए। अब इस आयु वर्ग के पेंशनर्स को कुल मिलाकर 77.50 फीसदी भुगतान हो जाएगा। बाकी 22.5 फीसदी आने वाले समय में दिया जाएगा।

सीएम ने देहरा में घोषणा की थी कि 75 और इससे अधिक आयु वाले पेंशनर्स को एरियर दे दिया जाएगा। उस समय सीएम ने एकमुश्त शब्द का प्रयोग नहीं किया था। लिहाजा ये समझा जा रहा था कि किस्तों में एरियर मिलेगा और वैसा ही हुआ भी है। बुजुर्ग पेंशनर्स को तो सरकार से कुछ राहत मिल गई है, अब कर्मचारी इंतजार में हैं।

• बोले सीएम...

ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का 2025 के अंत तक निर्माण होगा पूरा...

शिमला : सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा सचिवालय में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोलन के नालागढ़ में निर्माणाधीन एक मेगावाट क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए निविदा शीघ्र आवंटित की जाए और वर्ष 2025 के अंत तक प्लांट के निर्माण कार्य को पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की जाए। सीएम कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

यह ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उद्योगों में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग निरंतर बढ़ रही है। परिवहन, विनिर्माण और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन का एक स्वच्छ विकल्प देता है। शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ हरित हाइड्रोजन के उत्पादन से यह परियोजना उद्योगों और ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा जिससे पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। सुक्खू ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी होगी।

इससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा और पारिस्थितिकी तंत्र की भी रक्षा होगी। पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 20 माह के अपने कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को एक स्वच्छ और हरित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक नवाचार कदम उठाए हैं। इस दिशा में उन्होंने चंबा में 14 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन की पायलट परियोजना की आधारशिला रखी है। इसके अलावा, जिला ऊना के पेखूबेला में 32 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

अगले छह महीनों में दो और सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू होने की उम्मीद है। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, सलाहकार अधोसंरचना अनिल कपिल, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम के निदेशक शिवम प्रताप सिंह भी मौजूद रहे।

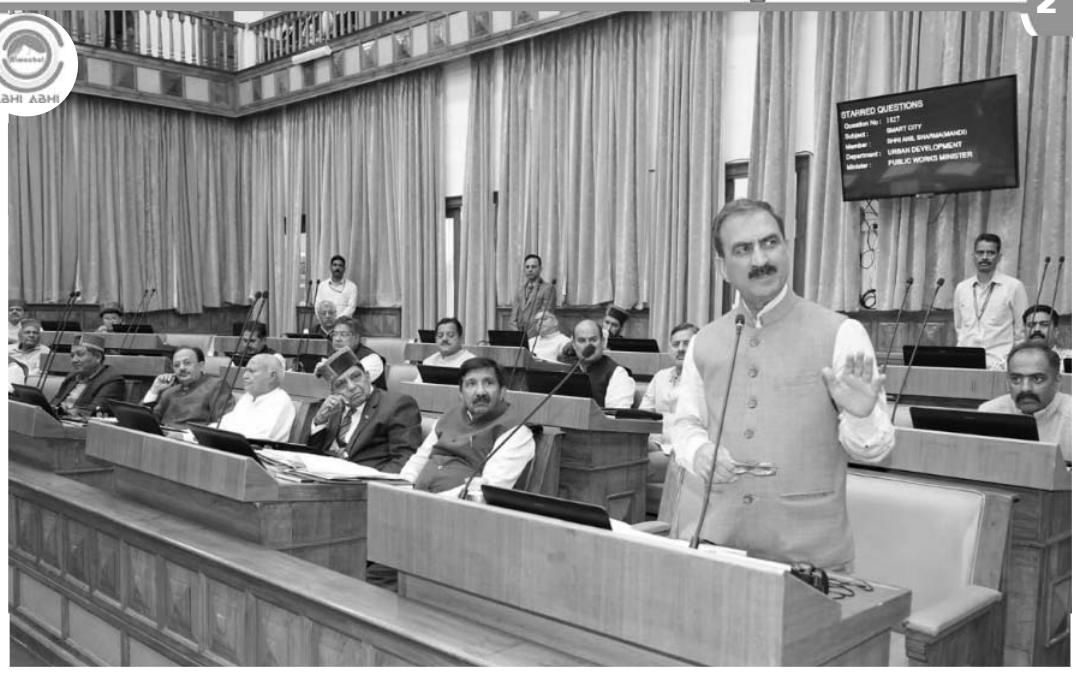

सीएम, मंत्रियों और सीपीएस के वेतन-भत्ते दो महीनों के लिए विलंबित

उन्होंने कहा कि प्रदेश की विषम वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों व मुख्य संसदीय सचिवों सहित अपने वेतन–भत्ते दो माह तक विलंबित करने का फैसला लिया है।

इसके अतिरिक्त आप सभी सदस्यों से भी अपने वेतन एवं भत्ते स्वेच्छा से विलंबित करने का आग्रह करता हूं। सीएम ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं...

● संजू/शिमला

हिमाचल प्रदेश में सीएम, मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों के वेतन-भत्ते दो महीने के लिए विलंबित होंगे। यानी बाद में मिलेंगे। विधायकों ने भी ऐसा करने का आग्रह किया। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को हिमाचल विधानसभा सदन को इस संबंध में प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विषम वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों व मुख्य संसदीय सचिवों सहित अपने वेतन-भत्ते दो माह तक विलंबित करने का फैसला लिया है। इसके अतिरिक्त आप सभी सदस्यों से भी अपने वेतन एवं भत्ते स्वेच्छा से विलंबित करने का आग्रह करता हूं। सीएम ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं। राजस्व घाटा अनुदान जो वर्ष 2023-24 में 8,058 करोड़ रुपये था। इस वर्ष 1,800 करोड़ कम होकर 6,258 करोड़ रुपये हो गया है।

अगले वर्ष (2025-26) में यह 3,000 करोड़ रुपये और कम होकर 3,257 करोड़ रुपये रह जाएगी। पीडीएनए की लगभग 9,042 करोड़ रुपये की राशि में से केंद्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। एनपीएस एनपीएस अंशदान के लगभग 9,200 करोड़ रुपये पीएफआरडीए से प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसका हम केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं। जीएसटी मुआवजा जून 2022 के बाद मिलना बंद हो गया है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 2,500-3,000 करोड़ की आय कम हो गई है। ओपीएस बहाल करने के कारण हमारी उधार भी लगभग 2,000 करोड़ से कम कर दी गई है। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। सीएम ने आगे कहा कि हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और अनुत्पादक व्यय कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा।

सीएम सुक्खू विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले पांच साल पूर्व भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से सरकारी खजाने को लुटाया वह शर्मनाक है। प्रदेश की विषम वित्तीय स्थिति के लिए पिछली भाजपा सरकार जिम्मेदार है। अभी जो वित्तीय स्थिति है, पहले कभी प्रदेश में नहीं हुई। हमारे आर्थिक प्रबंधन से आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। राजस्व बढ़ाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। मैं चाहता हूं कि प्रदेश के सभी वर्गों, अधिकारियों और कर्मचारियों का इसमें सरकार को सहयोग मिले। अगले वित्तीय वर्ष में सरकार आर्थिक हालात पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगी।

❖ पिछले पांच साल में पूर्व भाजपा सरकार ने सरकारी खजाने को लुटाया : मुख्यमंत्री

❖ अगले वित्तीय वर्ष में सरकार आर्थिक हालात पर काबू पाने में होगी कामयाब

सुक्खू ने कहा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं। आज मैं मुख्यमंत्री हूं, कल कोई और होगा। लेकिन, प्रदेश को वर्तमान वित्तीय हालात पर नहीं छोड़ा जा सकता। आर्थिक हालात ठीक करने के लिए कड़े निर्णय लेने ही होंगे, तभी युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा और रोजगार मिलेगा। हम अपनी सुधरी अर्थव्यवस्था पर ब्रेक नहीं लगा सकते, इसलिए और आर्थिक सुधारों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दो महीनों तक हमने वेतन-भत्ते नहीं लेने का फैसला लिया है। हमने सभी अधिकारियों को डीए और एरियर का बकाया देना है। आर्थिक स्थिति सुधरते ही इस पर निर्णय लेंगे।

बड़े होटलों की एक रुपये बिजली सब्सिडी बंद

सीएम ने कहा कि हमने आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए बड़े होटलों की एक रुपये बिजली सब्सिडी बंद कर दी है। बीते कल यह निर्णय लिया गया है। पूर्व बीजेपी सरकार ने शराब ठेकों के आवंटन में पांच साल में मात्र 665 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। जबकि कांग्रेस सरकार ने एक साल में ही ठेकों की नीलामी नए सिरे से कर 485 करोड़ रुपये की कमाई की है। भाजपा सरकार में रहे आबकारी मंत्री को जवाब देना चाहिए कि पांच साल में ठेकों की नीलामी क्यों नहीं हुई? क्यों ठेके रिन्यू किए जाते रहे। क्या यह महा घोटाला नहीं था।

• एक्शन...

50 हजार रिश्वत के साथ डीएम गिरफ्तार

नाहन : हिमाचल प्रदेश में नाहन में राज्य वन निगम के डिवीजनल मैनेजर को स्टेट विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बीती शाम को 50 हजार रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। डिवीजनल मैनेजर ने ठेकेदार से रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और गिरफ्तार किया। विजिलेंस ने नाहन थाने में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना के अनुसार, वन निगम के ठेकेदार के 67 लाख रुपए से भी ज्यादा के बिल पेंडिंग है। लंबे समय से ठेकेदार इन्हें क्लियर करने की मांग कर रहा था, और वन निगम कार्यालय के चक्कर काट रहा था। जिसके एवज में डिवीजनल मैनेजर ने ठेकेदार से रिश्वत मांगी और तब जाकर बिल का भुगतान करने की बात कही। बताया जा रहा है डीएम ने पेमेंट रिलीज करने की एवज में 2 फीसदी कमीशन डिमांड रखी थी। शुक्रवार को ठेकेदार ने 50 हजार रुपए की पहली किश्त डीएम को दे दी थी। इस दौरान वहां सादे लिबास में मौजूद विजिलेंस टीम ने आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर दिया।

• गैस रिसाव से ब्लास्ट...

बद्दी : बरोटीवाला के तहत झाड़माजरी में एलपीजी के रिसाव के बाद हुए ब्लास्ट में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रैफर कर दिया है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। धमाका इतना जोरदार था इसकी गूंज जहां काफी दूर तक सुनाई दी वहीं इससे कमरे में रखा फ्रिज फट गया और कमरे की दीवारें व रैलिंग भी ढह गई। सूचना मिलते ही एसपी बद्दी इल्मा अफ रोज ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया।